पूंजीवाद के पास नहीं है हल : मानव विकास की समस्याओं का

□ ई० बालानन्दन

हैदराबाद में हमारे (सी आइ टी यू) दसवें महाधिवेशन के बाद की अवधि में साम्राज्यवादी हमले बढ़े हैं; पूंजीवाद का भूमण्डलीय संकट बढ़ा है; भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की गति मंद हुई है; आर्थिक सुधारों को लागू करने के प्रयासों में तेजी आई है और भगवाकरण की कार्यसूची को जोर-शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है। देश भर में श्रमिक वर्ग पर हमले तेज हुए हैं जिनका संयुक्त प्रतिरोध भी बढ़ा है।

शासन की डोर निगमों के हाथ में

द हिन्दु ने 3 अगस्त, 2001 को संसद में हुई बहस की रिपोर्ट प्रकाशित की थी; रिपोर्ट का शीर्षक था : ''सरकार का नियंत्रण निगमों के हाथ में''। रिपोर्ट में कहा गया है कि ''आज लोक सभा में यू एस-64 घोटाले पर हुई बहस से देश में राजनीतिक आर्थिकता के सम्बन्ध में शिक्षाप्रद सीख मिली है। एक के बाद एक सभी वक्ताओं ने अपने दलगत विभाजनों से ऊपर उठकर उन भयावह शक्तियों एवं अधिकारों की ओर संकेत किया जिनका उपयोग करके नैगम घराने सरकार को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। जिस नैगम घराने का सर्वाधिक उल्लेख किया गया वह ''रिलायंस'' था...। आल्वी ने उल्लेख किया कि नैगम घराने इस सीमा तक शक्तिशाली हो गये हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा और कौन अधिकारी किस मंत्रालय का सचिव बनेगा, इसका निर्णय लेने की स्थिति में वे आ गए हैं। इसके पश्चात् उन्होंने सीधे वित्त मंत्री पर प्रहार किया; उन्होंने वित्त मंत्री को सम्बोधित करते हुए कहा, ''आप इसलिये वित्त मंत्री बने हैं क्योंकि 'वे' नहीं चाहते थे कि कोई और वित्त मंत्री बने।''

इस रिपोर्ट को पढ़ने से आप को पता चल जाएगा कि इस देश के शासन का संचालन करने वालों की वास्तविक प्रकृति क्या है...क्योंकि मंत्रियों, सचिवों तथा उनके विभागों से सम्बन्धित निर्णय नैगम घरानों के आकाओं द्वारा लिया जाता है। भारतीय लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप यही है।

अमरीका में जार्ज डब्ल्यू बुश ने सत्ता में आने के तत्काल पश्चात् दो घोषणाएं की थीं जो पूरे विश्व के लिये चिंता का विषय बनी हुई हैं। एक वे 1972 की ए बी एम संधि का पालन नहीं करेंगे और ''अपने राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा कार्यक्रम'' को पूरा करने के लिये आगे की कार्रवाई करेंगे। और दूसरे—क्वोटो प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर तथा उसका अनुमोदन करने से सम्बन्धित अपनी प्रतिबद्धता से मुंह मोड़ लेने का निर्णय।

राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा कार्यक्रम

यह दावा किया गया था कि ''शत्रु राज्यों'' से ''अमरीकी सीमाओं'' की रक्षा करने और देश के बाहर अमरीका के ''विशेष हितों'' की रक्षा के लिये एन एम डी व्यवस्था की नितांत आवश्यकता है। इस पर 800 अरब अमरीकी डालर खर्च होने का अनुमान था। यद्यपि इसकी सम्भावनाएं एवं व्यवहार्यता अब भी संदेह से परे नहीं है; इसके अतिरिक्त विश्व भर में इसका विरोध बढ़ रहा है; विरोध करने वाले देशों में नाटो के सहयोगी देश भी सम्मिलित हैं तथापि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वर्तमान में विश्व के एक सौ से भी अधिक देशों में अमरीका ने अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर रखे हैं। इनमें से अधिकांश अड्डे फारस/अरब की खाड़ी की सीमाओं के साथ-साथ और पूर्वी यूरोप, बालकान, कोरिया तथा जापान सहित पूरे यूरोप में हैं। मादक पदार्थों के विरुद्ध संघर्ष संघर्ष करने वाले योद्धा (भाड़े के) केन्द्रीय अमरीका, कोलम्बिया, इक्वेडोर तथा पेरू में डेरा डाले बैठे हैं। अमरीका में स्थापित बड़े इजारेदार निगमों के व्यापार हितों की सुरक्षा करने के साथ-साथ विश्व भर में सैन्य बलों को भेजकर उनके पेट्रोल तथा खनिजों जैसे सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पदार्थों को अपने (अमरीकी) नियंत्रण में लिया जाता है। चीन पर दृष्टि रख कर भारत सहित सम्पूर्ण एशिया-प्रशांत क्षेत्र में उनके (अमरीकी) सैन्य अड्डों को और अधिक मजबूत बनाने के लिये इन दिनों जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं। चीन तथा रूस ने प्रस्तावित मिसाइल रक्षा प्रणाली के विरुद्ध अपना तीखा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने पारस्परिक सुरक्षा, सहायता एवं सहयोग के लिये एक दीर्घावधि की संधि पर हस्ताक्षर किये हैं।

क्योटो प्रोटोकोल

वर्ष 1997 के क्योटो प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करने से अमरीका का इन्कार विश्व के देशों को एक साथ मिल कर भूमण्डलीय तापमान में वृद्धि होने जैसे गम्भीर प्रश्न पर कदम उठाने के लिये सहमति बनाने से रोक नहीं सका। 186 देशों जिनमें से 38 औद्योगिक देश हैं, के प्रतिनिधियों की एक बैठक संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में बोन (जर्मनी)

में हुई। उसी बैठक में इस प्रोटोकोल पर सहमति हुई थी और उस पर हस्ताक्षर किये गए थे। यह प्रोटोकोल वर्ष 2002 तक प्रभावी होगी और इस पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् 55 देशों ने इसे अपने राष्ट्रीय कानून का एक भाग बना लिया है; इन देशों में 55 प्रतिशत प्रदूषित और गैस छोड़ने वाले औद्योगिक देश भी सम्मिलित हैं। अमरीका द्वारा विरोधी किये जान पर भी यह सहमति बनी; इससे अमरीका के अलग-थलग पड़ने का संकेत ही मिलता है। विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के पच्चीस प्रतिशत भाग का उत्सर्जन अथवा स्राव अकेले अमरीका की ओर से होना है जबकि वहां विश्व भर की जनसंख्या का केवल चार प्रतिशत भाग रहता है। बिना किसी रोक टोक के पुराने जीवाष्म ईंधनों का उपयोग करने से सम्बन्धित इमरीका की नयी ऊर्जा नीति ग्रीन हाउस गैसों के स्राव के उसके भाग को और बढ़ा देगी। इसलिये विश्व के तापमान को गर्म करने वाली गैसों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिये विश्व भर की जनता का कर्त्तव्य बन जाता है कि वह अमरीका को इस बात के लिये तैयार करने के लिये उस पर सामुहिक दबाव डाले।

बढ़ रहे विरोध के स्वर

जी-8 देशों के शिखर सम्मेलन से पूर्व जिनोआ (इटली) में पूंजीवादी भूमण्डलीयकरण के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रदर्शनों ने सिएटल की भांति पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। जार्ज डब्ल्यू बुश, टोनी ब्लेयर, सि ल्वो बर्लुस्कोनी तथा सात अन्य अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्यवादी देशों के प्रमुखों के साथ-साथ रूस के व्लादिमिर पुतिन ने 19-22 जुलाई 2001 को सम्पन्न इस बैठक में भाग लिया था।

इटली की पुलिस द्वारा अवरोध खड़े किये जाने पर भी लाखों लोगों ने इन प्रदर्शनों में भाग लिया; उन्होंने राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी; ये लोग यूरोप भर से आए थे और भिन्न व्यवसायों के साथ सम्बन्ध रखते थे। प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा भाग इटली के श्रमिकों एवं युवाओं का था; उनमें कम्युनिस्ट तथा अनेक गैर सरकारी संगठनों के कार्यकर्ता भी सम्मिलित थे। एक 24 वर्षीय युवक कार्लो गुइलियानी को सड़क पर गोली मार दी गई; दो गोलियां उसके सिर में छेद करते हुए निकल गईं और वह घटनास्थल पर ही दम तोड़ गया। पूंजीवादी भूमण्डलीयकरण के विरुद्ध संघर्ष करने वाला वह पहला युवक था जिसने इस संघर्ष में अपने जीवन की आहुति दे दी थी। यह भी पता चला है कि इटली की सीमा पार करते हुए एक फ्रांसिसी महिला गोली लगने के कारण मारी गई; वह प्रदर्शन में भाग लेने के लिये इटली में प्रविष्ट हो रही थी। इसके अतिरिक्त सैकड़ों लोग घायल अथवा गम्भीर रूप से घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख नारों में से एक था : पूंजीवाद मुर्दाबाद!

अत: ये प्रदर्शन इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि श्रमिक वर्ग अपनी पंक्तियों में एकता ला रहा है और पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध अपने संघर्ष को तीव्र से तीव्रतर कर रहा है। विकसित पूंजीवादी समाजों में संकट बढ़ रहा है; लाखों लोगों का दरिद्रीकरण हो रहा है; इसके विपरीत धन सम्पदा मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में सिमटती चली जा रही है; इसके फलस्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध लोगों में रोष एवं आक्रोश व्यापक स्तर पर बढ़ रहा है। इस प्रकार की आंदोलनात्मक गतिविधियां चलाने का उद्देश्य भी यही है। इन प्रदर्शनों ने न केवल लोगों की व्यापक श्रेणियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है अपितु उनका जुझारूपन भी बढ़ रहा है। श्रमिक तथा युवा वर्ग इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

यहां पर हम विशेष रूप से उल्लेख करेंगे कि इस प्रकार के प्रदर्शनों के फलस्वरूप विश्व बैंक के उच्च पदस्थ अधिकारियों तथा उनके साम्राज्यवादी प्रभुओं में घबराहट उत्पन्न हो गई है। विश्व बैंक का सम्मेलन 25-27 जून को बार्सिलोना में होना निश्चित हुआ था; उसे रद्द कर देना पड़ा क्योंकि उसके विरुद्ध भी विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम बन चुका था। अत: पूंजीवाद के विरुद्ध एक नये प्रकार के विरोध की कार्रवाईयां होने लगी हैं।

पूंजीवाद का भूमण्डलीय संकट

विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर गहरे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाल ही तक वे यह शेखी बघारते थकते नहीं थे कि "वे संकट मुक्त पूंजीवाद" की स्थापना कर देंगे और वही एकमात्र चिरस्थायी व्यवस्था होगी। वे कहते थे कि हाई टैक के इस युग में संकट चक्र का सिद्धांत पुराना पड़ चुका है और वह अब वैध नहीं रहा; यह उनका दावा था जो अब खोखला सिद्ध हो चुका है।

विश्व की शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं अर्थात् अमरीका तथा जापान जो मिलकर विश्व में 46 प्रतिशत उत्पादन करते थे, मंदे की दलदल में धंस चुके हैं जबकि यूरोपीय देशों की अर्थ व्यवस्था में तेज गिरावट आ रही है। इसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। पिछले एक वर्ष में स्टाक मार्किट सर्वत्र लड़खड़ा चुकी हैं। भूमण्डलीय शेयर मूल्यों में ये लगभग 100 खरब डालर निकल चुके हैं। एन ए एस डी ए क्यू को भी भयानक संकट का सामना करना पड़ा (सूचना प्रौद्योगिक शेयर)।

विश्व की दो सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थ व्यवस्थाओं अमरीका तथा जापान में आए इस मंदे का दुष्प्रभाव उनके निर्यातों पर भी पड़ा है।

अन्य एशियाई देशों में भी इसकी गम्भीर प्रतिक्रिया होगी क्योंकि उनका 37 प्रतिशत निर्यात अमरीका तथा जापान में होता है।

चीन इसमें अपवाद बना हुआ है। इस वर्ष उसकी विकास दर 8

(शेष पृष्ठ 8 पर)

उस नौजवान कार्लो गुइलियानी को याद करो जिसे जिनोआ में इटली की पुलिस ने गोली मार कर मृत्यु की गोद में सुला दिया था; वह नौजवान इसलिये मारा गया क्योंकि वह पूंजीवादी भूमण्डलीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहा था। याद करो इस नये नारे को जिसने पूरे यूरोप में कम्पकपी सी पैदा कर दी है। यह नारा है—पूंजीवाद मुर्दाबाद!

सी आइ टी यू कार्य समिति की बैठक

एन डी ए सरकार देश को विनाश की गहरी खाई में धकेल रही है...!

□ एम के पन्धे

केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार देश को अमरीकी साम्राज्यवाद की झोली में डाल देने के लिये उन्मत प्रयास कर रही है, वह बहुत जल्दबाजी से काम ले रही है। भारत की विदेश नीति में जो कुछ भी साम्राज्यवाद विरोधी अन्तर्वस्तु है, उसे वाजपेयी सरकार एक एक करके मिटाती चली जा रही है। भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह इस दिशा में सुनियोजित ढंग से प्रयास कर रहे हैं, हमारी विदेश नीति अमरीका समर्थक बन जाए, बस यही चाह उनके भीतर बलवती है। अमरीका के साथ सामरिक गठबंधन करने की बातों का क्षेत्र व्यापक हो चुका है, देश का सैनिक क्षेत्र भी अब इसकी चपेट में आ गया है और इसके अन्तर्गत देश के उत्तरी-पूर्वी भाग के जंगलों का उपयोग अमरीकी साम्राज्यवादियों की प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, करने की अनुमति दे दी जाएगी। डिआगो गार्शिया में अमरीकी अड्डे के बारे में भारत का विरोध वापस ले लिया गया है। अब तो भारत की धरती पर भी अमरीका की सैनिक उपस्थिति पर भारत की सरकार को कोई आपत्ति नहीं रही, वह इसके लिये सहमत हो गई है। जब सभी युरोपीय शक्तियां और यहां तक कि जापान भी न्यूक्लीयर मिसाइल डिफैंस प्लैन (एन एम डी पी) का विरोध कर रहा है तब भारत सरकार चीनी खतरे की दुहाई देकर इस योजना का स्वागत कर रही है, इस मामले में वह सठिया ही गई है। जब चीन तथा रूस के मध्य एन एम डी पी का विरोध करने के लिये पारस्परिक सहमति हो चुकी है तब भारत की भूमिका से इस क्षेत्र की स्थिति और अधिक खराब होगी, इसमें संदेह नहीं। अनेक अमरीकी अधिकारी भारत की यात्रा कर रहे हैं, इनमें रक्षा अधिकारी भी सम्मिलित हैं, वे यहां आकर भारत सरकार से अपनी शर्तें मनवाते हैं और वाजपेयी सरकार का प्रवक्ता उनके निदेशों के आगे नतमस्तक होता चला जाता है। इसके फलस्वरूप भारत की सम्प्रभुता तथा स्वतंत्रता को क्षति पहुंच रही है। अमरीका अपने आर्थिक प्रतिबंधों को समाप्त कर देगा, इस कोरी आशा में भारत सरकार अनुचित ढंग से अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रभुओं को प्रसन्न करती चली जा रही है।

इसके परिणामस्वरूप गुट निर्पेक्ष आंदोलन के देशों में भारत की प्रतिष्ठा कम हो रही है। अमरीकी साम्राज्यवाद के समक्ष इस समर्पण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन की परभक्षी लूट के विरुद्ध विकासशील देशों को एकजुट करने तथा अपने-अपने हितों की रक्षा करने के प्रयास शिथिल पड़ रहे हैं अथवा उन्हें धक्का लग रहा है।

पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरि तथा असम में पिछले मई में हुआ चुनावी युद्ध सत्तारूढ़ एन डी ए सरकार तथा उसकी नीतियों के लिये एक बड़ी चुनौती था। सत्तारूढ़ गठबंधन को इन सभी राज्यों में पराजय का मुंह देखना पड़ा था। इसका समग्र रूप में हमारे राष्ट्रीय परिदृश्य पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है।

भारत-पाक वार्ता

भारत के प्रधान मंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति के मध्य 15-16 जुलाई 2001 को सम्पन्न आगरा शिखर वार्ता के फलस्वरूप भारत तथा पाकिस्तान की जनता में नयी आशाओं ने जन्म लिया था। प्रचार माध्यमों में इसका बढ़ चढ़ कर प्रचार किया गया और उन्मादपूर्ण स्थिति उत्पन्न की गई।

इससे पूर्व वाजपेयी सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर में युद्धबंदी की घोषणा कर दी थी किन्तु कश्मीर समस्या का समाधान करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई। युद्धबंदी की अवधि बढ़ाने से भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। फिर भी पाकिस्तान के सैनिक शासक परवेज मुर्शरफ को सीधी बातचीत के लिये निमंत्रण देना एक सकारात्मक कदम था। यद्यपि शिखर वार्ता विफल रही और उसके अपेक्षित परिणाम नहीं निकले तथापि दोनों देशों के मध्य बातचीत अवश्य शुरू हुई है। भारत के प्रधान मंत्री द्वारा पाकिस्तान की यात्रा का निमंत्रण स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप बातचीत की यह प्रक्रिया जारी रहेगी। क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर की बातचीत का केंद्रीय मुद्दा बनाने के लिये हठ करता रहा था इसलिये इस शिखर वार्ता का कोई निष्कर्ष निकल नहीं सका। पाकिस्तान चाहता था कश्मीरी जनता की इच्छाओं के अनुरूप समस्या का समाधान खोजा जाए जबकि भारत सीमा पार से प्रायोजित आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने की मांग कर रहा था।

आगरा शिखर वार्ता का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं हो सका, दोनों देशों के कट्टरपंथी तत्व इस विफलता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, वे लोगों की भावनाओं को भड़का कर तनाव की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। पाकिस्तानी समर्थन प्राप्त चरम पंथियों ने जम्मू एवं कश्मीर में अपने हमले तेज कर दिये हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिन्दुओं में शावनवादी भावनाएं भड़का रहा है। गृह मंत्री लाल कृष्ण अडवाणी ने खुले रूप में जम्मू एवं कश्मीर को न्यायोचित स्वायत्ता देने की मांग ठुकरा दी है।

साम्राज्यवादी अभिकरण जम्मू एवं कश्मीर को साम्प्रदायिकता के आधार पर तीन भागों में बांट कर इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण रखने वाले सभी लोगों को दृढ़तापूर्वक इन कुत्सित प्रयासों का विरोध करना होगा।

भारत में कश्मीर समस्या का समाधान करने के लिये आवश्यक कदम तत्काल उठाए जाने चाहियें, यह काम जम्मू एवं कश्मीर को न्यायोचित स्वायत्ता प्रदान करके तथा समस्या के समाधान हेतु अनुकूल वातावरण बना कर उठाए जाने चाहिए। इस मामले में और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

मणिपुर की ज्वालाएं

भारत सरकार ने जब नगालैंड में युद्धबंदी को मणिपुर, असम, मेघालय तथा अरूणांचल प्रदेश तक बढ़ाने की घोषणा कर दी तब मणिपुर की जनता में भीषण आक्रोश की लहर दौड़ गई थी। एन डी ए सरकार ने सम्बंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श किये बिना ही एन एस सी एन (आइ-एम) के साथ युद्धबंदी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये थे। मणिपुर की जनता ने इसका हिंसक प्रतिवाद किया क्योंकि वे समझते थे कि यह समझौता मणिपुर राज्य को तोड़ने और केंद्रीय सरकार द्वारा विशाल नगालैंड की मांग मान लेने की भूमिका अथवा पूर्वाभ्यास है। उनके विरोध की लहर इस सीमा तक बढ़ गई कि इसी मध्य मणिपुर विधान सभा को जला डाला गया और अनेक विधायकों पर हमले किये गए। पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण 12 व्यक्ति मारे गए जिसकी मणिपुर में भारी प्रतिक्रिया हुई।

अंतत: एन डी ए सरकार को उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किये जाने के पश्चात् नगालैंड के बाहर युद्धबंदी का क्षेत्र बढ़ाने की अपनी घोषणा से पीछे हट जाने के लिये विवश होना पड़ा। पूर्व गृह सचिव पद्मनाभय्या जिनकी युद्धबंदी समझौते को अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका रही थी, को बदल देना पड़ा। नागालैंड का प्रश्न एन एस सी एन (आइ एम) के साथ बातचीत करके सुलझाया जाना चाहिये किन्तु यह काम पड़ोसी राज्यों की जनता के मूल्य पर कदापि नहीं किया जा सकता। यही नहीं, एन एस सी एन (आइ एम) को कह दिया जाए कि वह त्रिपुरा सहित अन्य सभी समीपवर्ती राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों के लिये सहायता देना बंद करे।

विदेशी गुप्तचर अभिकरण भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं। इन गतिविधियों के विरूद्ध सजग रहना अत्यावश्यक है क्योंकि इनका उद्देश्य देश की एकता तथा अखण्डता को खण्डित करना है।

शिक्षा का भगवाकरण

एन डी ए के कार्यक्रम की भी अनदेखी करते हुए भाजपा शिक्षा का भगवाकरण करने की दिशा में आगे की कार्रवाई कर रही है, इसके दुष्परिणाम भयानक होंगे और दीर्घावधि तक इन दुष्परिणामों का प्रभाव बना रहेगा। ज्योतिष विज्ञान को विश्व विद्यालयों में एक विषय के रूप में सम्मिलित कराया जा रहा है, यह एक उल्लेखनीय मामला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग सभी शैक्षणिक संस्थानों में अत्यंत प्रमुख (आधारभूत) पदों पर आसीन हो चुके हैं। शैक्षणिक विधियों में वैदिक कर्मकाण्ड को प्रमुखता दी जा जा रही है। पाठ्य पुस्तकों तथा पाठ्य क्रमों को बदला जा रहा है, इतिहास का मिथ्याकरण किया जा रहा है और सम्पूर्ण शैक्षणिक ढांचे की प्रकृति का साम्प्रदायीकरण किया जा रहा है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की धर्मनिर्पेक्ष प्रकृति पर यह एक गम्भीर हमला है जिसे हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आज तक बनाए रखा था। इसके दुष्परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक और अधिक उदासीन हो जाएंगे, वे पहले ही स्वयं को भारत में असुरक्षित अनुभव करने लगे हैं।

अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना

भाजपा तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ खुले रूप में अल्पसंख्यकों पर हमले कर रहे हैं और उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर रहे हैं। राजस्थान में दो मसजिदों के अपमान एवं ध्वंस करने की घटनाओं के पीछे स्पष्ट रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं का हाथ था, वे लोग राज्य में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करना चाहते थे। गुजरात तथा अन्य राज्यों मं हाल ही में ईसाई धर्म के प्रचारकों पर जो हमले हुए हैं वे भाजपा समर्थक तत्वों द्वारा कराए गए थे। पुलिस ने भी भाजपाई गुण्डों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने से इन्कार कर दिया था।

विश्व हिन्दू परिषद ने अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण करने के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की है, उसकी यह कार्रवाई अत्यंत उत्तेजक है। किन्तु भाजपा ने इस प्रश्न पर मौन साध रखा है और वह इन नीतियों को उत्साहित कर रही है। इस प्रकार की कार्रवाईयां करने से केवल मुसलिम कट्टरपंथियों की अल्प संख्यकों को भयभीत करने का अवसर मिलेगा।

भाजपा द्वारा भारतीय मुसलमानों तथा ईसाईयों को खुले रूप में आह्वान किया गया है कि वे अपने हिन्दू अतीत को स्वीकार करें, इसका अर्थ केवल अल्पसंख्यक समुदायों को भड़काना ही है। एन डी ए में सम्मिलित गैर-साम्प्रदायिक दल भाजपा की इन घातक कार्रवाईयों में भागीदार बने हुए हैं, वे केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं ताकि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिये सत्ता का आनंद ले सकें। उन्हें धर्म निर्पेक्ष दल के रूप में जो प्रतिष्ठा मिली थी उस पर उनके लापरवाही वाले इस आचरण के चलते पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है।

दलितों तथा महिलाओं पर हमले

देश में दलितों तथा महिलाओं पर हमले बढ़ रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में जहां भाजपा का शासन है, पिछले वर्ष 400 से अधिक दलित महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। यह संख्या देश भर में दलित महिलाओं के साथ हुए बलात्कारों की घटनाओं की कुल संख्या का आधा भाग है। एक लड़के तथा लड़की की केवल इसलिये घृणित ढंग से हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने अलग-अलग जातियों से सम्बन्ध रखते हुए भी प्रेम विवाह कराने का अपराध किया था, यह घृणित हत्या गांव के अनेक लोगों की उपस्थिति में हुई थी। देश की स्थिति कितनी दु:खदायी है, इस घटना से यह संकेत मिल जाता है।

उच्च जाति के सवर्ण हिन्दु शावन वादियों द्वारा दलितों की हत्याएं नित्य प्रतिदिन की घटनाएं बन चुकी हैं। अनेक हत्याएं भूमि पर कब्जे

के प्रश्न पर की गईं। इन अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने में प्रशासन की विफलता से उन्हें और उत्साह मिलता है तथा वे बार-बार ये अपराध करने लग जाते हैं। हमारा अनुभव दर्शाता है कि केवल मात्र दलितों को आरक्षण दिये जाने से ही उनके विरुद्ध इन अत्याचारों को कम नहीं किया जा सकता। एन डी ए सरकार निर्लज्जतापूर्वक समाज में उच्च जाति के बर्चस्व को बढ़ावा दे रही है, इसके फलस्वरूप देश में दलितों तथा महिलाओं पर होने वाले ये हमले और तीव्र हो जाएंगे।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय को यौन उत्पीड़न को पारिभाषित करने तथा अपराधियों को दण्डित करने के लिये कानून बनाने का निदेश दिया था किन्तु श्रम मंत्रालय ने केवल यौन उत्पीड़न को पारिभाषित किया है और वह भी सरसरी ढंग से। कामकाजी महिलाओं के विरुद्ध होने वाले इन अपराधों के लिये दण्ड देने का सुझाव स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। क्योंकि यौन उत्पीड़न की बहुत घटनाएं होने लगी हैं और इनमें से अधिकांश मामलों में कोई गवाही नहीं मिलती, इसलिये कामकाजी महिलाओं के लिये अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न को सिद्ध करने के मार्ग अनेक कठिनाईयां आड़े आती हैं। इस प्रकार के अपराधों के विरूद्ध अधिकारी गम्भीरतापूर्वक कार्रवाई नहीं करते।

एन डी ए शिविर में अस्थिरता

तहलका घोटाले से एन डी ए गठबंधन को करारा झटका लगा है, उसके फलस्वरूप भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण तथा केंद्रीय रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस को अपने-अपने पदों से त्यागपत्र देना पड़ा। भाजपा द्वारा इस घोटाले की एन डी ए सरकार के विरूद्ध एक षड्यंत्र के रूप में निरूपित करने का प्रयास किया गया किन्तु इस पर भी जन साधारण ने भाजपा के प्रचार पर विश्वास नहीं किया। यदि एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था, किन्तु वह स्पष्ट रूप में एन डी ए सरकार की करतूतों पर पर्दा डालने की एक चाल है। कुछ बरिष्ठ सैनिक अधिकारियों को भी टेलीविजन के पर्दे पर रक्षा सौदे में घूस लेते देखा गया। इससे उस खतरनाक षड्यंत्र की पोल खुल जाती है जो देश के संवेदनशील रक्षा क्षेत्र में किया जा रहा है, इसके फलस्वरूप स्वयं एन डी ए सरकार की प्रतिरक्षा सम्बन्धी मामलों में कार्यक्षमता पर भारी संदेह उत्पन्न होते हैं।

तृणमूल कांग्रेस तथा पी एम के का विधान सभा चुनावों से पूर्व एन डी ए से बाहर निकलना और चुनावों के बाद पुन: एन डी ए में लौट आना इस गठबंधन की क्षणभंगुर प्रकृति को रेखांकित करता है। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों में जाट मतदाताओं को अपनी ओर आकृष्ट करने के लियें अजीत सिंह को जिस ढंग से शामिल किया गया, वह सर्वथा सिद्धान्तहीन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इसका खुला विरोध किया है।

मणिपुर की घटनाएं जहां भाजपा तथा समता पार्टी दोनों की ओर से दलबदली का नाटक खेला गया था, अंतत: समता पार्टी सरकार के पतन का कारण बनी और उसके स्थान पर भाजपा द्वारा सरकार बनाने की तत्परता दिखाई गई, समता पार्टी ने जब इससे रुष्ट होकर एन डी ए छोड़ने की धमकी दे डाली तो उनके मध्य एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत राज्य में सरकार नहीं बनाने का निर्णय लिया गया और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। मणिपुर संकट ने एन डी ए गठबंधन की भीतरी अस्थिरता को जग जाहिर कर दिया है।

इस प्रकार के प्रत्येक संकट में तेलगु देशम पार्टी एन डी ए सरकार को जारी रखने के लिये अपना मूल्य लेती रही है। प्रत्येक संकट में चन्द्रबाबू नायडु की मनचाही परियोजनाओं के लिये भारी भरकम राशि देना अब एक सामान्य सी बात बन चुकी है। जब कभी एन डी ए संकट में पड़ता है तब तब अकाली दल भी अपनी कीमत वसूल करता रहा है। ममता बनर्जी द्वारा समय समय पर त्यागपत्र देने के लिये धमकियां दी जाती रहीं और भाजपा मौखिक रूप में उसकी मांगों को स्वीकार करती रही, एन डी ए में ये बातें सामान्य बन चुकी हैं। यद्यपि वह एक बार पुन: एन डी ए में शामिल हो रही है, किन्तु वह कब तक गठबंधन में रहेगी यह प्रश्न संदेह से परे नहीं है, स्वयं भाजपा नेताओं ने भी इस पर अपने संदेह व्यक्त किये हैं।

शिव सेना सांसद संजय निरूपम ने हाल ही में यू टी आइ घोटाले में प्रधानमंत्री कार्यालय के शामिल होने को लेकर जो बावेला मचाया था, उसके चलते प्रधानमंत्री को त्याग पत्र की धमकी देने के लिये विवश होना पड़ा था। शिव सेना ने महाराष्ट्र में भाजपा के साथ अपना गठजोड़ समाप्त करने की खुली धमकी दी है। शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे ने धमकी दी है कि यदि भाजपा अपनी नीति के लिये हठ करती रही तो शिव सेना एन डी ए से बाहर आ जाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय पर अपने आरोपों को पुन: दोहराते हुए कहा कि वह पर्दे के पीछे देश का शासन चला रहा है।

भाजपा संसदीय दया की एक बैठक में अनेक सांसदों ने वित्त मंत्री पर उनकी नीतियों को लेकर हमले किये थे जिस पर प्रधानमंत्री को उनकी रक्षा करने के लिये आगे आना पड़ा। उमा भारती का यह वक्तव्य कि राम विलास पासवान भारत के भावी प्रधान मंत्री होंगे और भाजपा सांसदों द्वारा उनकी आलोचना करना, इस बात का संकेत है कि भाजपा के भीतर जातिवादी ध्रुवीकरण बढ़ रहा है।

भाजपा सरकार सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से देश को विनाश की गहरी खाई में धकेल रही है। इस बेढंगे गठबंधन को सत्ता से निकाल बाहर करने के लिये जितनी जल्दी जन संघर्षों को तेज किया जाएगा, देश के लिये उतना ही अच्छा होगा।

(पृष्ठ 5 का शेष)

प्रतिशत से भी अधिक रहने की सम्भावना है क्योंकि उनका निर्यात उनके सकल घरेलू उत्पाद का केवल 23 प्रतिशत भाग है। वे हाई-टैक निर्यातों पर बहुत कम निर्भर करते हैं।

विकसित देशों में आयात प्रतिबंधित होता है जबकि वे आक्रामक ढंग से निर्यात करते हैं और वह भी विशेष रूप से तृतीय विश्व के देशों में। संकट मुक्त पूंजीवादी व्यवस्था का निर्माण करने का दावा झूठा सिद्ध हुआ है। पूंजीवाद के पास मानव विकास की समस्याओं का कोई हल ही नहीं है। □

उद्योगवार महासंघों की कार्यप्रणाली

उद्योगवार महासंघ श्रमिकों की जागरूकता के स्वर को कारखाना स्तर के तंग गलियारे से निकाल कर उद्योगवार गतिविधियों के व्यापक स्तर तक ऊंचा उठाने में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं।

उद्योगवार महासंघों की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धि श्रमिक संघों का संयुक्त मंच बनाने के विचार को मूर्त रूप देना तथा औद्योगिक श्रमिकों के संयुक्त आंदोलन का विकास करना है। इसके फलस्वरूप श्रमिक वर्ग के देश व्यापी संयुक्त आंदोलन के निर्माण में और अधिक योगदान दिया जा सका है। इसकी एक गौरवमयी उदाहरण सी पी एस टी यू है। शायद औद्योगिक श्रमिकों का कोई भी दूसरा संयुक्त मंच सी पी एस टी यू की भांति इतने लम्बे समय तक अपने सक्रिय अस्तित्व को बनाए रख सका हो।

सी आइ टी यू के महासंघ

हमारे ग्यारह उद्योगवार महासंघ हैं जैसे (1) इस्पात, (2) बागवानी, (3) जल परिवहन, (4) कोयला, (5) निर्माण, (6) सड़क परिवहन, (7) विद्युत, (8) चीनी, (9) जूट (पटसन), (10) आंगनवाड़ी तथा (11) बीड़ी। इन ग्यारह उद्योगवार महासंघों में से चीनी श्रमिकों का अखिल भारतीय महासंघ तथा अखिल भारतीय जूट श्रमिक महासंघ व्यवहारिक रूप से समाप्त प्राय: हो चुके हैं यद्यपि इन दोनों उद्योगों में इनकी उद्यम स्तरीय यूनियनें बहुत सक्रिय हैं। जहां तक अन्य महासंघों का सम्बन्ध है, उनमें बागवानी श्रमिकों के अखिल भारतीय महासंघ तथा अखिल भारतीय सड़क परिवहन श्रमिक महासंघ की बैठकें नियमित रूप से नहीं होतीं। दोनों महासंघों की अधिकांश बैठकें बहुत थोड़े समय के लिये होती हैं और सामान्यतया ये बैठकें सी आइ टी यू के महाधिवेशन/बैठकों के समय होती हैं। सड़क परिवहन श्रमिकों के अखिल भारतीय महासंघ ने अब इस कार्य प्रणाली को त्याग दिया है। महासंघों की कार्य समितियों की बैठकें सामान्यतया वर्ष में दो बार होती हैं और उनमें उपस्थिति लगभग 60-65 प्रतिशत रहती है। अधिकांश मामलों में ये बैठकें लिखित रिपोर्ट के बिना होती हैं और बैठकों के लिये समुचित तैयारी भी नहीं की जाती। इन बैठकों में प्राय: उन समस्याओं तथा कार्यक्रमों पर विचार किया जाता है जो अत्यंत आवश्यक होते हैं।

कार्य प्रणाली के मुद्दे

हमारा अनुभव दर्शाता है कि इन महासंघों के अधिकांश पदाधिकारी जिनमें मुख्यालयों के साथी भी सम्मिलित हैं, दूसरे श्रमिक संघों में अपने अन्य कार्यक्रमों के दृष्टिगत सम्बन्धित महासंघ के कार्यों पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाते। उद्योग के विभिन्न केन्द्रों में जाने का काम तो यदाकदा ही होता है। जब तब इन महासंघों के कार्यों की समुचित ढंग से योजना नहीं बनाई जाएगी और उन कार्यक्रमों को सुनिश्चित नहीं बनाया जाएगा तब तक अखिल भारतीय महासंघ प्रभावी ढंग से अपना काम नहीं कर सकेंगे। उद्योग के भीतर काम करने वाले सुयोग्य साथियों का विकास किया जाना चाहिए और उन्हें महासंघों के कामों पर विशेष रूप से लगाया जाना चाहिए। इन साथियों को उनके स्थानीय दायित्वों से मुक्त करना आवश्यक है।

लगभग सभी महासंघों के कामों पर विशेष रूप से लगाया जाना चाहिए। इन साथियों को उनके स्थानीय दायित्वों से मुक्त करना आवश्यक है।

लगभग सभी महासंघों के मुख्यालय सर्वाधिक सुदृढ़ सांगठनिक आधार वाले स्थानों में स्थित हैं और या उन स्थानों पर जहां महासंघ के महासचिव रहते हैं। नियुक्त होते हैं। यह भी समझ है कि नयी दिल्ली में स्थापित मुख्यालय अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। तथापि गोदी एवं बंदरगाह जैसे उद्योग के मामले में उसके मुख्यालय का स्थान मुम्बई हो सकता है—जो उद्योग की गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है।

"इन महासंघों की गतिविधियों का अच्छे ढंग से निरीक्षण करने की आवश्यकता है। हमें अपने काम के इस पक्ष की ओर अधिक ध्यान देना होगा तथा उद्योगवार गतिविधियों को देखने का दायित्व राज्यों के नेताओं को देना होगा। राज्य में उद्योगवार गतिविधियों के फलस्वरूप अखिल भारतीय महासंघ और सुदृढ़ होगा।" —भुवनेश्वर दस्तावेज़

अपने गठन के प्रारम्भिक चरण में हमारे अनेक महासंघों ने कमजोर माने जाने वाले क्षेत्रों में संगठन बनाने/उसका विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। किन्तु उन प्रयासों की निरंतरता को बनाए नहीं रखा जा सका। महासंघों के केन्द्र की प्रभावशाली कार्य प्रणाली इस सम्बन्ध में असाधारण योगदान दे सकती हैं।

सी आइ टी यू के साथ सम्बन्ध श्रमिक संघों ने अनेक उद्योगों में लम्बे संघर्षों के पश्चात् सौदेबाजी करने वाले मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इन संघर्षों ने हमारे कुछ उद्योगवार महासंघों को जन्म भी दिया है। किन्तु उन उद्योगों में सौदेबाजी करने वाले श्रमिक संघों का दर्जा मिलने से भी हमें उन उद्योगों में अपने सांगठनिक आधार

(शेष पृष्ठ 14 पर)

सी आइ टी यू कार्य समिति की बैठक

राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी करो

यद्यपि केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने बहुत समय पूर्व अर्थात् मई 2001 में हड़ताल की देशव्यापी कार्रवाई करने का आह्वान किया था, किन्तु उसकी तिथि की घोषणा नहीं की जा सकी। प्रायोजन समिति के घटक संगठन हड़ताल की कार्रवाई करने के लिये तैयार हैं किन्तु इंटक तथा बी एम एस के नेतृत्व में अखिल भारतीय हड़ताल की तिथि का निर्धारण करने के लिये अपनी सहमति नहीं दी है। बी एम एस के नेतृत्व ने संकेत दिया है कि वह हड़ताल की राज्यव्यापी अथवा उद्योगवार हड़ताल की अखिल भारतीय कार्रवाई करने के लिये तो तैयार हैं किंतु राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिये नहीं। उनके अनुसार इस सम्बन्ध में अभी कुछ और तैयारियां करना आवश्यक है।

अनेक राज्य स्तरीय सम्मलेलनों में पारित प्रस्तावों से देशव्यापी हड़ताल की कार्रवाई के लिये समर्थन के संकेत मिलते हैं। तथापि अभी तक हड़ताल की तिथि का निर्धारण करना सम्भव नहीं हो सका है। इंटक तथा बी एम एस के नेतृत्व ने हड़ताल के अतिरिक्त किसी अन्य कार्रवाई में भाग लेने के लिये अपनी तत्परता व्यक्त की है। इस संघर्ष का एक संयुक्त कार्यक्रम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो उन्हें भी स्वीकार्य हो। हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के संघर्ष के कार्यक्रम में हम उन्हें अवश्य सम्मिलित कर सकेंगे। तथापि भारत सरकार अपनी विनाशक नीतियां बदले; इस उद्देश्य से उस पर दबाव डालने के लिये हड़ताल की राष्ट्रव्यापी कार्रवाई करने की नितांत आवश्यकता हे। हमें आशा है कि हम सभी घटकों को एकजुट कर सकेंगे और अब तक हमने श्रमिक आंदोलन में जिस एकता का निर्माण करने में हमने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। श्रमिक वर्ग भी इस एकता को और अधिक सुदृढ़ बनाना चाहता है।

इसके साथ ही साथ हमें राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने के प्रश्न पर श्रमिक आंदोलन के नेतृत्व के कुछ भाग के संकोच को भी दूर करना होगा। हड़ताल का आह्वान पहले ही किया जा चुका है और उसकी तिथि की घोषणा करना होगा। हड़ताल का आह्वान पहले ही किया जा चुका है और उसकी तिथि की घोषणा करना अभी शेष है। इसलिये, हमें भारत भर में सभी स्तरों पर इसका प्रचार करने के काम पर विशेष रूप से बल देना होगा और व्यापक प्रचार करना होगा ताकि राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिये संयुक्त रूप से आह्वान करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। उस संघर्ष की अन्य कार्रवाईयों के लिये संयुक्त रूप से काम करते समय हमं अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से एक सफल अखिल भारतीय हड़ताल के लिये अभियान चलाने पर भी बल देना होगा।

यदि हम श्रमिक वर्ग की सभी श्रेणियों में इसके लिये सफल प्रचार अभियान चला पाते हैं तो हम निश्चित रूप से राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिये संयुक्त रूप से आह्वान करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे जिसमें पहले ही असाधारण देरी हो चुकी है।

अहमदाबाद के दिहाड़ी मजदूरों की शानदार जीत

अहमदाबाद (गुजरात) म्युनिसिपल कार्पोरेशन के इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत करीब 200 दिहाड़ी मजदूरों को तुगलकी मानसिकता के सत्ताधीशों ने अचानक काम से हटा दिया। हटाए गए मजदूरों में 41 सुपरवाइजर भी शामिल हैं। ये मजदूर पिछले करीब सात वर्षों से कार्यरत थे।

उल्लेखनीय है कि गुजरात इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के निर्णयानुसार लगातार पांच वर्षों तक नियमित काम अथवा इन पांच वर्षों में कम से कम 900 दिन काम करने वाले मजदूरों-कर्मचारियों को स्थायी जगह व नियमित काम दिए जाने का प्रावधान है। इस निर्णय का पालन करते हुए अहमदाबाद म्युनिसिपल कार्पोरेशन ने भी अधिकृत रूप से नीतियां बनाई हैं। लेकिन मज़दूरों को उपर्युक्त न्यायिक सुरक्षा मिली होने के बावजूद भाजपा को पराजित करके हाल में कार्पोरेशन में सत्तारूढ़ हुई कांग्रेस पार्टी ने मजदूरविरोधी कदम उठाया है।

नौकरी से हटाए गए मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कामदार-कर्मचारी यूनियन (सीटू) के नेतागण आनंदभाई परमार, भूपेंद्र पुरोहित तथा जयंतीभाई सोलंकी के नेतृत्व में इन मजदूरों को संगठित कर आंदोलन शुरू किया गया।

इस आंदोलन के तहत अहमदाबाद म्युनिसिपल कार्पोरेशन मुख्यालय पर लगातार 15 दिनों तक धरने व प्रदर्शन आयोजित किए गए। मजदूरों को डरा-धमका कर उनकी एकता तथा आंदोलन को तोड़ने के लिए सत्ताधारियों ने हथियारबंद गुंडों व निजी सुरक्षाकर्मियों, पुलिस तथा सरकारी खुफिया तंत्र का खुला इस्तेमाल किया। इसके बावजूद इंजीनियरिंग विभाग में सक्रिय यूनियन के प्रद्युमन मेहता के नेतृत्व में सुपरवाइजरों ने बढ़-चढ़ कर आंदोलन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले मजदूरों-कर्मचारियों को डराने-धमकाने के लिए सत्ताधारियों ने वीडियोग्राफी भी करवाई, लेकिन मजदूर-कर्मचारी अडिग